पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 19, अंक 2/2018

प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने का आह्वान

प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से मानव जीवन के साथ-साथ वन्य जीवों और पालतू पशुओं पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि इन थैलियों में फलों व सब्जियों के छिलके व अन्य खाद्य वस्तुएं बांधकर कचरे में बाहर फेंक दी जाती है। उन्हें गाय व अन्य पशु थैली सहित खा जाते हैं। इससे वह असमय मौत के शिकार तक हो जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कई बदलाव लाने होंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'कट्स' द्वारा जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में आयोजित 'प्लास्टिक मुक्त' कार्यक्रमों में खासतौर पर यह उभरकर सामने आया। जयपुर में सम्पन्न विचार गोष्ठी में लोकसभा सदस्य रामचरण बोहरा ने हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे वर्ष प्रयास करने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए नुक्कड़ नाटक व बाल सभाओं का आयोजन कर जागरूकता संदेश दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल ने कहा कि हम कपड़े या जूट का थैला लेकर बाजार जाने की पुरानी परम्परा को भूल चुके हैं। हमें इस परम्परा को वापस अपनाना होगा। हमें अपने परिवार को बताना चाहिए कि प्लास्टिक थैलियां व अन्य सामान कचरे में न फैंक कर कबाड़ी वाले को दें, ताकि वह री-साईकिल हो सके और उसे गाय व अन्य जानवर नहीं खा सके। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने गायों को प्लास्टिक से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प लिया।

इसके अलावा 'कट्स' द्वारा मणिपाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 'कट्स' के ग्रासरूट प्रभारी शांतनु श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमरदीप सिंह ने संस्था का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीवास्तव ने बताया कि प्लास्टिक किस तरह से भूजल स्तर को दूषित करता है और इसे पूर्णतया मिट्टी में परिवर्तित होने में एक हजार साल लग जाते हैं। प्लास्टिक को पानी में बहाने से वह पुनः भोज्य पदार्थों के माध्यम से मानव के पेट में पहुंच कर उन्हें रोगग्रस्त कर देता है।

उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं फेकल्टी सदस्यों को प्लास्टिक से बने विभिन्न उत्पादों का कम उपयोग करने, पुर्नउपयोग करने और री-साईकिल पर जोर देते हुए विश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शपथ दिलाई।

इसी क्रम में 'कट्स' मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ और ग्राम पंचायत नेतावलगढ़ पाछली के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर 'प्लास्टिक मुक्त भारत में समुदाय की भूमिका' विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए नेतावलगढ़ पाछली के सरपंच रामेश्वर लाल धाकड़ ने प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसानों पर प्रकाश डाला।

गोष्ठी में 'कट्स' के केंद्र समन्वयक गौहर महमूद ने पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने का संदेश दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। गोष्ठी में उपस्थित कई अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी सहभागियों ने अपने घर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया।

इस अंक में...

- बाजार में बेच खाया गरीबों का राशन 3
- नोट गिनने की मशीन खरीद में गड़बड़ 4
- भ्रष्टाचार में राजस्थान की छठी रैंक 5
- मुद्रा योजना से 12 करोड़ लोगों को फायदा 7
- पानी का गंभीर संकट-नीति आयोग 9

हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचना आवश्यक

केन्द्र सरकार की योजनाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का दायित्व और हमारा कर्तव्य है। पहले संपन्न व्यक्ति ही बीमा पॉलिसी ले पाते थे लेकिन अब गरीब से गरीब आदमी भी मात्र 12 रुपए में अपना बीमा करवा सकता है।

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सहयोग से संचालित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण परियोजना के तहत 'कट्स' द्वारा किसान भवन, चित्तौड़गढ़ में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद सी.पी.जोशी ने उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने हर तहसील से एक गांव को शत-प्रतिशत वित्तीय साक्षरता और माइक्रो इंश्योरेंस योजना से जोड़ने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवाओं के बारे में हर व्यक्ति को सचेत और जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने इंटरनेट सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण महिलाओं में इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सचिन बाडेटिया ने समाज के हर तबके के लोगों को सूक्ष्म बीमा योजनाओं से जोड़ने की जरूरत बताई। तकनीकी सत्र में विभिन्न बैंकों से आए अधिकारियों ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक के शुरुआत में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने परियोजना के उद्देश्यों एवं गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रथम चरण में जिले की 11 पंचायत समितियों की 1854 महिलाओं को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बैठक में जिले की सभी पंचायत समितियों की ग्रामीण महिलाओं सहित 104 सहभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

छात्रों को दी जैविक खेती एवं उत्पादों की जानकारी

'कट्स' द्वारा प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना की गतिविधियों के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर की मूंडिया रामसर पंचायत के सेंट पॉल मार थोमा स्कूल में आयोजित परिचय बैठक में जैविक गार्डन विकसित करने की जानकारी दी गई। यह गार्डन बच्चों एवं विद्यालय के सहयोग से विकसित किया जाएगा। जैविक गार्डन विकसित करने का उद्देश्य बच्चों व आमजन को जैविक खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है। जैविक गार्डन विकसित करने के लिए 'कट्स' संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जाएगा।

इस अवसर पर 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने जैविक खेती के महत्व के बारे में बच्चों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जर्वेशन के सहयोग से राजस्थान के 10 जिलों में प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से जैविक खेती एवं सतत उपभोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 'कट्स' के कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारीक ने जैविक खेती को विकसित करने की तकनीकी जानकारी दी। जैविक गार्डन का शुभारंभ स्कूल के निदेशक फादर सेमसन सेम्यूअल ने किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों की ओर से स्कूल कैम्पस में फलदार पौधे भी लगाए गए।

'कट्स' को बनाया उपभोक्ता परिषद का सदस्य

केंद्र सरकार ने 'कट्स' इंटरनेशनल को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में बतौर सदस्य पुन: नियुक्त किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 3 के उपनियम (1) की अनुपालना के अन्तर्गत गठित इस समिति में केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान के उपभोक्ता मामलात विभाग के सचिव को भी शामिल किया गया है। परिषद उपभोक्ताओं के लिए सरकार को सुझाव देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 'कट्स' परिषद में राजस्थान के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेगा और परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न नीतियों में संशोधन कराने का प्रयास करेगा।

महिला सुरक्षा फंड नहीं हुआ खर्च

महिला सुरक्षा के नाम पर वन स्टॉप सेंटर (सखी केन्द्र) खोलने के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्र की ओर से मिलने वाला फंड वापस लौट गया है। फंड वापस आने के पीछे प्रमुख कारण राजस्थान सरकार द्वारा इन धनराशि का उपयोग नहीं करना है। इसके बावजूद केंद्र ने राज्य सरकार को दोबारा धनराशि जारी कर काम पूरा करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करने के मकसद से देशभर में सखी केंद्र योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। राजस्थान सरकार को इस योजना के तहत सखी केन्द्र खोलने के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 3 करोड़ 36 लाख 21 हजार 750 रुपए स्वीकृत किया गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस वित्तीय वर्ष में इस फंड का उपयोग ही नहीं किया।

(रा.प., 07.05.18)

आवंटित करोड़ों, कौड़ी भी खर्च नहीं

केन्द्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। इन योजनाओं के लिए आवंटित होने वाली पूरी धनराशि का उपयोग ही नहीं हो पाता। सरकार की कौशल विकास योजना के लिए साल 2016-17 के लिए 157.75 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, लेकिन खर्च एक कौड़ी भी नहीं हुआ।

इसी तरह से साल 2017-18 के लिए कौशल विकास के लिए 238.15 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ जिसमें से महज 11 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। युवा उद्यमियों के विकास और ट्रेनिंग सेंटर के लिए करीब 10 करोड़ रुपए के आवंटन के बावजूद एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। इसी तरह कई योजनाओं के लिए बजट में राशि तो आवंटित हुई पर पूरा पैसा खर्च ही नहीं हुआ। *(रा.प., 10.05.18)*

आदर्श गांव सिमटे कागजों में

सांसद और विधायकों के आदर्श गांव घोषित कर सरकार ने मंशा जाहिर की थी कि इन गांवों में विकास तो होगा साथ ही ऐसी आदर्श व्यवस्थाएं भी कायम होंगी जो अन्य गांवों के लिए मिसाल बनेंगी। इसके विपरीत हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार की नियमित विकास योजनाओं की राशि को ही व्यय बता कर दर्शाया जा रहा है।

अब मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है। सरकार को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। मसलन, कितने विधायकों ने आपने गांव को सपनों का गांव बना दिया एवं कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव को आदर्श बनाने में कोई रुचि नहीं ली।

(रा.प., 26.04.18)

सड़क बनी नहीं, कर दिया भुगतान

जो सड़क अभी बनी नहीं है, उसे गुणवत्ता परीक्षण में खरा मान कर उसका भुगतान कर दिया गया। भ्रष्टाचार का यह खेल राष्ट्रीय राजधानी प्लानिंग बोर्ड में शुरु हो चुका है। करीब 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत है, लेकिन बोर्ड के पैकेज तीन के विजय मंदिर-पड़ीसल-खैरथल-हरसौली रोड़ में यह कारनामा कर दिया गया।

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पैकेज तीन के तहत खैरथल में मतौर रोड़ से हरसौली रोड़ तक बाइपास पर सीसी रोड़ बनाया जा रहा है। अभी रोड़ की एक तरफ की पट्टी भी पूरी नहीं हुई है और इंजीनियरों ने 1.3 किलोमीटर सड़क का करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। जबकि नियमानुसार मापदंड पर खरा उतरने पर भुगतान किया जाता है।

(रा.प., 12.04.18)

आबकारी विभाग वसूली में सुस्त

प्रदेश में आबकारी विभाग की डिफॉल्टर शराब ठेकेदारों पर बकाया राशि अब 132 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बकाया राशि के ज्यादा मामले वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2010-11 तक की अवधि के हैं। विभाग के बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद ठेकेदार यह बकाया राशि जमा नहीं करा रहे।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार शराब ठेकेदार विभाग के डिपो से माल उठाते रहे। ठेका समाप्त हुआ तो उन्होंने बकाया राशि जमा नहीं कराई। बढ़ते हुए बकाया राशि 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मूल रकम की तो वसूली हो, इसके लिए ब्याज माफी की 'आबकारी एमनेस्टी योजना' 2002 से अब तक 4 बार लाए, लेकिन अब भी 132 करोड़ रुपए की वसूली बकाया है। *(दै.भा., 23.06.18)*

मनरेगा मजदूरी में राजस्थान पीछे

मनरेगा की मजदूरी के मामले में राजस्थान देश के 17 राज्यों से पीछे है। प्रदेश में वर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 192 रुपए प्रतिदिन ही रखी गई है। बीते साल 2017-18 में भी मनरेगा मजदूरों को इतनी ही मजदूरी मिल रही थी। यानी इस साल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 213 रुपए प्रतिदिन रखी है, जबकि मनरेगा मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। *(दै.भा., 07.04.18)*

बाजार में बेच खाया गरीबों का राशन

प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में रसद विभाग के अधिकारियों व राशन डीलरों ने मिलीभगत कर 60235.82 क्विंटल राशन का गेहूं बाजार में बेच दिया। जिसकी कीमत 9 करोड़ 95 लाख 77 हजार 312 रुपए बताई जा रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तत्कालीन डीएसओ सुनिल वर्मा, कार्यवाहक डीएसओ व एडीएम भागीरथ शर्मा, तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक विजेंद्र पाल, पवन सुथार, देवेंद्र आसारी, बाबूलाल जानू व निशा सहारण के खिलाफ दोषी मानते हुए मामला दर्ज किया है।

सबसे ज्यादा पीलीबंगा तहसील में 29805.60 क्विंटल व रावतसर तहसील में 9982 क्विंटल गेहूं का घोटाला हुआ है। गेहूं के आवंटन में शिकायत आने के बाद तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने भी दो माह का आवंटन नहीं किया था और राशन डीलरों से ही गेहूं रिकवरी करवाकर बांटने का आदेश दिया था। *(दै.भा., 31.05.18)*

नोट गिनने की मशीन खरीद में गड़बड़

केंद्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में दो साल पहले हुई नोट गिनने की 40 मशीनों की खरीद में बड़ी अनियमितता सामने आई है। जो मशीन बाजार में जीएसटी को मिलाकर 1.48 लाख में मिल रही थी, वही मशीन बैंक में जीएसटी मिलाकर 2.50 लाख रुपए में खरीद ली गई। इस तरह हर मशीन पर एक लाख रुपए ज्यादा खर्च किए गए। इस पूरे मामले में कानफेड की भूमिका संदिग्ध है। क्योंकि मशीनों की खरीद कानफेड के जरिए ही की गई थी।

इस खरीद को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज हुई। एसीबी ने जांच के लिए पत्र लिखा तो कानफेड और सहकारी बैंक भरतपुर में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि भरतपुर के अलावा अन्य 32 जिलों में भी नोट गिनने की मशीनों की खरीद कानफेड के जरिए ही हुई थी। *(दै.भा., 22.04.18)*

तीस हजार करोड़ के बैंक फर्जीवाड़े

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक ही साल में 30 हजार करोड़ रुपए के बैंक फर्जीवाड़े हो गए। बैंकों में बढ़ते फर्जीवाड़े बैंकिग तंत्र को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं। यह खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) से बखूबी हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकों को फर्जीवाड़े के 6000 मामलों से 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगी है। वित्त वर्ष 2016-17 में फर्जीवाड़े के 12533 मामलों में 18,170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फर्जीवाड़ों में ज्यादातर हिस्सा सरकारी बैंकों का है। लगभग 85 फीसदी फर्जीवाड़े के मामले सरकारी बैंकों में हुए हैं। कर्ज में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 65 फीसदी की ही है। *(रा.प., 28.06.18)*

उजाड़े 17 हजार पेड़, हरियाली गायब

जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानोता से दौसा तक उजाड़े 17 हजार पेड़ों की जगह लगाए गए पौधे टोल वसूलने वाली कंपनी की लापरवाही से 10 साल बाद भी पनप नहीं सके हैं। हरे-भरे पेड़ों से लकदक रहने वाला यह राजमार्ग आज हरियाली विहीन है। जो पौधे लगाए गए, वह या तो जमींदोज हो चुके हैं या दो फीट से ज्यादा नहीं बढ़े हैं।

राजमार्ग पर खानिया से कानोता तक के 10 किलोमीटर क्षेत्र में तो एक भी पेड़ नहीं है, वहीं कानोता से दौसा तक 40 किलोमीटर लंबा मार्ग कंपनी की लापरवाही भुगत रहा है। कंपनी को दोगुने पेड़ लगाने की शर्त पर ही 17 हजार पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कंपनी दस साल में एक भी पेड़ नहीं पनपा सकी। *(रा.प., 30.04.18)*

सामने आया लोक सेवा गारंटी का सच

प्रदेश में लोगों को विभिन्न कार्यालयों में सरकारी सेवा समय पर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन पिछले सात सालों में अफसरों ने इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई है। इन सात सालों में समय पर काम नहीं होने की 5.81 करोड़ शिकायतें सरकार के पास पहुंची।

सात सालों में इतनी शिकायतें आना काफी गंभीर मामला है। इनमें से अभी भी 1.33 लाख शिकायतें पेंडिंग बताई जा रही है। जबकि अधिनियम में काम पूरा करने की अवधि तय है। तय अवधि में काम पूरा नहीं होने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। समय पर काम नहीं होने की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद महज 23 हजार 500 रुपए का ही जुर्माना अफसरों पर लगाया गया है। *(दै.भा., 18.04.18)*

केंद्रीय योजनाओं में हुई कटौती

केंद्र सरकार से योजनाओं को लेकर सतत संपर्क व लगातार दबाव नहीं बनाए जाने के कारण राजस्थान को आर्थिक मोर्चे पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रदेश में केंद्र की सहायता से चलाई जा रही योजनाओं में करीब 5000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में केंद्रीय सहायता के तौर पर 20800 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि वित्त वर्ष के अंत तक सिर्फ 15775 करोड़ रुपए ही मिले हैं।

केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रदेश को मिलने वाली राशि में इतनी ज्यादा कटौती पहली बार की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार जिन योजनाओं में केंद्र से पैसा ले सकती थी वह भी नहीं लिया गया। *(दै.भा., 25.04.18)*

मरीजों की सेहत से हो रहा खिलवाड़

प्रदेश में जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित एकमात्र सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में स्टाफ की कमी के चलते दवाओं के नमूनों की पेंडिंग जांच छह हजार तक पहुंच चुकी है। लैब में करीब 74 से 58 पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं। लैब में नमूनों की जांच का इंतजार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है।

जहां वर्ष 2010-11 में 644 नमूने पेंडिंग रहे थे, वहीं अब 2017-18 में 6000 नमूने जांच की बाट जोह रहे हैं। इसके चलते कई बार दवाओं की जांच में साल भर लग जाता है और रिपोर्ट आने तक हजारों मरीजों तक अमानक और नकली दवाएं पहुंच चुकी होती है। इससे नकली दवाओं के कारोबार को रोकने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। *(दै.भा., 04.05.18)*

जेडीए में अब मिट्टी घोटाला

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में अबकी बार मिट्टी के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। यह मिट्टी चोरी जेडीए के आला अफसरों की मिलीभगत से रिंग रोड सीमा के आस-पास हो रही है। सरकारी जमीनों पर जेडीए ने जो प्लाट रिजर्व कर रखे हैं उन रिजर्व प्लाटों से कई बीघा में अवैध मिट्टी का खनन हो चुका है और यह मिट्टी ठेकेदार जेडीए को ही बेच रहे हैं।

शिकायतों का मेजरमेंट कराया तो केवल एक ही जोन की सीमा में 40 लाख के अवैध खनन का खुलासा हुआ है। जेडीए की तीनों शाखाओं, इंजीनियर, एनफोर्समेंट और जोन की ओर से सैंकड़ों बीघा में अवैध मिट्टी खनन की बात को स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन कार्रवाई की बात की जाती है तो अधिकारी बगले झांकने लगते हैं। *(दै.भा., 15.06.18)*

स्विस बैंकों में बढ़ा 50 फीसदी धन

स्विस बैंक की एक रिपोर्ट ने नोटबंदी से कालेधन की कमी का दावा करने वाली केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। इसके मुताबिक स्विस बैंकों में भारतियों का धन 50 प्रतिशत बढ़कर 2017 में लगभग 7000 करोड़ रुपए हो गया है। इनमें सीधे तौर पर रखा गया धन लगभग 6891 करोड़ रुपए है।

इसके अलावा भारतियों ने अपने प्रतिनिधियों या धन प्रबंधकों के जरिए 112 करोड़ रुपए जमा कराए। स्विस बैंकों में भारतियों का सबसे ज्यादा धन 2006 के अंत तक 23000 करोड़ रुपए जमा था। एक दशक में यह तीसरी बार है जब स्विस बैंकों में भारतियों के पैसे में वृद्धि हुई है। 2011 में कुल जमा धन में 12 प्रतिशत, 2013 में 43 प्रतिशत और 2017 में 50.2 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई थीं। *(रा.प.एवं दै.भा., 29.06.18)*

केस दर्ज 4474, सजा सिर्फ 112 को

प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने वर्ष 2007 से 2017 तक रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग और आय से अधिक सम्पत्ति रखने के 4474 केस दर्ज किए। इनमें से 2367 मामलों में कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी। इनमें से 587 मामलों में केस दर्ज करने के बाद एफआर लगानी पड़ी।

कुछ मामलों में एफआर विभागों से आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने पर लगानी पड़ी तो कुछ मामलों में एसीबी के पास ठोस सबूत नहीं थे। इनमें वे मामले भी शामिल हैं, जिनमें एसीबी ने अफसर-कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही 1540 प्रकरणों में पुलिस अफसरों की कमी होने से जांच पेंडिंग बताई गई है। एसीबी की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। गत 10 सालों में वह महज 112 लोगों को ही भ्रष्टाचार के आरोप में सजा दिला पाई है। *(दै.भा., 25.04.18)*

कैदी दे रहे डॉक्टरों को मंथली घूस

जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों को शुद्ध दूध सप्लाई करने की एवज में जेल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मंथली 2000 रुपए की घूस दिए जाने का मामला सामने आया है। डॉक्टर बीमार कैदियों को जेल में बिना मिलावट दूध देने के बदले हर माह अपने बैंक खाते में उनके परिजनों से दो-दो हजार रुपए जमा करा रहे थे।

इसकी भनक जेल विभाग के कार्यवाहक डीजी भूपेन्द्र सिंह यादव को लगी तो उन्होंने तत्काल जेल के हॉस्पिटल से दो डॉक्टरों को हटा दिया। अब किस डॉक्टर के बैंक खाते में कितना पैसा जमा हुआ है इसकी जांच की जा रही है। *(दै.भा., 07.04.18)*

जीतें 5 करोड़ तक के ईनाम

भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से अर्जित धन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक विदेशों में कालेधन की जानकारी देने पर आयकर विभाग 5 करोड़ रुपए तक ईनाम देगा। देश में बेनामी संपत्ति की सूचना देने वाले को एक करोड़ रुपए तक का ईनाम दिया जाएगा। देश में कर चोरी की पुख्ता सूचना देने पर 50 लाख रुपए तक का ईनाम दिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बेनामी लेनदेन सूचनार्थी पुरस्कार योजना 2018 का ऐलान किया है। जानकारी आयकर विभाग की बेनामी लेनदेन निषेध इकाई के संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त को दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

(रा.प.एवं दै.भा., 02.06.18)

काली कमाई कानून पर काला पर्दा

भ्रष्ट मंत्री और अधिकारियों की काली कमाई पर स्कूल-अस्पताल चलाने की मंशा पर राज्य सरकार ने ताला लगा रखा है। विधानसभा की मंजूरी के बाद छह साल पहले कानून लागू हो चुका है, लेकिन सरकार काली कमाई वाले मामले ही तय नहीं कर पाई। कानून का पालन कराने को जिम्मेदार अधिकारियों को मौजूदा स्थिति तक पता नहीं है।

कानून की स्थिति जानने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से लेकर सचिवालय व हाईकोर्ट तक पड़ताल की गई लेकिन हाईकोर्ट को छोड़कर किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है। अब तक विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं हुई थी। इसी कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हाल ही अब यह नियुक्ति कर दी गई है। *(रा.प., 09.04.18)*

बेनामी संपत्ति मामले में जयपुर अव्वल

आयकर विभाग ने पूरे देश में 4300 करोड़ रुपए की 1500 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई नए बेनामी कानून लागू होने के डेढ़ साल के भीतर हुई। जयपुर और मुंबई में सबसे ज्यादा 200-200 संपत्तियां जब्त की गई हैं। सबसे कम बेनामी संपत्तियां पटना में जब्त की गई।

आयकर विभाग के पास देशभर में 24 समर्पित बेनामी संपत्ति निषेध इकाइयां हैं। यह आयकर विभाग में प्रमुख जांच निदेशकों के नेतृत्व में काम करती हैं, ताकि इन पर तेजी से कार्रवाई की जा सके। दरअसल संशोधित बेनामी कानून के लागू होने के बाद से आयकर विभाग ने देशभर में बेनामी संपत्तियों के लेन-देन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। कानून में बेनामी संपत्ति पाए जाने पर कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। *(रा.प., 27.06.18)*

भ्रष्टाचार में राजस्थान की छठी रैंक

राजस्थान में 20 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी तरह की रिश्वत देनी पड़ी है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की 'इंडिया करप्शन स्टडी 2018' की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। सरकारी सेवाओं में रिश्वत देने के मामले में सर्वे में शामिल किए गए 13 राज्यों में राजस्थान छठे स्थान पर है।

हालांकि 2005 की तुलना में रिश्वत देने वालों का प्रतिशत घटा है। वर्ष 2005 में 58 फीसदी लोगों ने रिश्वत दी थी। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 20 फीसदी रह गया है। इसके उलट सर्वे में सामने आया है कि 51 प्रतिशत लोग मानते हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी बढ़ी है। प्रदेश की 51 प्रतिशत जनता मानती है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार कम नहीं कर पा रही।

(दै.भा., 20.05.18)

देश में 27 फीसदी लोगों ने दी रिश्वत

देश में सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए पिछले साल 12 महीनों में 27 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ी है। हालात यह है कि देश के महज 13 राज्यों में 11 सरकारी सेवाओं को हासिल करने के लिए लोगों को करीब 2800 करोड़ रुपए की घूस देनी पड़ी। इसमें अदालत में पसंद की तारीख लेने, पानी बिजली का कनेक्शन लेने, ट्रेफिक चालान से बचने, एफआईआर लिखवाने, जमीन जायदाद के कागजात लेने जैसे कामों के लिए घूस दी गई।

यह खुलासा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की 'इंडिया करप्शन स्टडी 2018' की जारी 12वीं रिपोर्ट में हुआ है। इस साल फरवरी-मार्च में देश के 13 राज्यों में किए गए अध्ययन में 75 फीसदी लोगों ने कहा कि देश में पिछले साल की तुलना में भ्रष्टाचार बढ़ा है या जस का तस रहा है। हालांकि नागरिक सक्रियता, आरटीआई, ऑनलाइन सुविधाओं और सोशल मीडिया के असर से 2005 की तुलना में 2018 में भ्रष्टाचार करीब 50 फीसदी तक घटा है। वर्ष 2005 में विभिन्न सेवाओं के लिए करीब 52 प्रतिशत लोगों को घूस देनी पड़ी थी। *(दै.भा., 19.05.18)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बीकानेर	राजेन्द्र सिंह	हैड कांस्टेबल, ग्रामीण बिजली चोरी निरोधक थाना	10,000	*दै.भा. एवं दै.न., 04.04.18*
राजसमंद	माधव सिंह सोलंकी दिनेश पालीवाल	थानाधिकारी, देलवाड़ा थाना, राजसमंद सरपंच, देलवाड़ा (मध्यस्थ)	20,000	*दै.भा. एवं दै.न., 04.04.18*
उदयपुर	हरकेश मीणा	हैड कांस्टेबल, गोवर्द्धन विलास थाना, उदयपुर	10,000	*रा.प., 16.04.18*
राजसमंद	महेश जोशी	थाना प्रभारी, चारभुजा पुलिस थाना, राजसमंद	40,000	*रा.प. एवं दै.न., 17.04.18*
श्रीगंगानगर	दिनेश यादव	पटवारी, नूरपुर हलका, सादुलशहर, श्रीगंगानगर	1,00,000	*रा.प., 17.04.18*
अजमेर	संजय जैन	पटवारी, हलका नून्द्रीमालदेव, ब्यावर	50,000	*रा.प.एवं दै.न., 17.04.18*
बारां	धीरेन्द्र कुमार सक्सेना अभिषेक सक्सेना	वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय उप पंजीयक, बारां डीड राइटर, कार्यालय उप पंजीयक, बारां	30,000	*दै.न., 01.05.18*
नागौर	कन्हैया लाल आचार्य	अपर लोक अभियोजक, एडीजे कोर्ट, परबतसर	8,000	*रा.प., 03.05.18*
जयपुर	रमन सिंह	हैड कांस्टेबल, पालड़ी मीणा चौकी, खोनागोरिया थाना	11,000	*रा.प. एवं दै.न., 04.05.18*
कोटा	अमजद खान	एएफओ, अग्निशमन विभाग, नगर निगम, कोटा	7,000	*रा.प. एवं दै.भा., 05.05.18*
बीकानेर	विजयशंकर जयपाल दीपक एवं मुकेश शर्मा	खनि अभियंता, अलवर में पद स्थापित जयपाल के दलाल (बीकानेर में मंगाई रिश्वत राशि)	5,98,000	*दै.भा. एवं रा.प., 07.05.18*
नागौर	शिवचरण खर्रा	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, गठिया	14,500	*रा.प., 12.05.18*
उदयपुर	रामलाल गुर्जर प्रेम सिंह	एएसआई, अम्बामाता थाना कांस्टेबल, अम्बामाता थाना	50,000	*दै.भा. एवं रा.प., 14.05.18*
बूंदी	कमलेश परमार मनीषा राजपुरोहित	जिला आबकारी अधिकारी आबकारी विभाग, बूंदी आबकारी निरीक्षक, आबकारी विभाग, बूंदी	2,50,000	*दै.भा. एवं रा.प., 17.05.18*
उदयपुर	दीपिका खटीक	पटवारी, बेदला पटवार मंडल	22,000	*दै.भा., 25.05.18*
बांसवाड़ा	पुरुषोत्तम बुनकर	एएसआई, कुशलगढ़ थाना, बांसवाड़ा	15,000	*दै.भा. एवं दै.न., 25.05.18*
जयपुर	जगदीश सैन	कनिष्ट लिपिक, नगर निगम आमेर, जयपुर	20,000	*रा.प. एवं दै.भा., 30.05.18*
झालावाड़	कपिल डी आसारसा	सहायक आयुक्त, वणिज्य कर विभाग	15,000	*दै.भा. एवं दै.न., 02.06.18*
बारां	मनीष मीणा	अधिशासी अधिकारी, अंता नगर पालिका	50,000	*दै.भा. एवं दै.न., 08.06.18*

समय पर मिले योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि वास्तविक रूप से हकदार कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे, उन्हें समय पर लाभ मिले।

राजे ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पात्रता का सत्यापन जरूरी है, लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया से उन लोगों तक लाभ पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए, जो पात्र है। पाली जिले के फालना बाली विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद के दौरान लाभार्थियों ने उन्हें बताया कि उनकी शुरू की गई योजनाओं से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। *(दै.न., 24.04.18)*

पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक बनें

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत और जागरूक रहने का आह्वान करते हुए कहा है कि हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी भावी पीढ़ी को सुखद वातावरण मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। पर्यावरण की अनदेखी का ही परिणाम है कि इन दिनों प्राकृतिक खतरे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को जहां तक संभव हो मूल स्वरूप में रखने की कोशिश करें। हम सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्लास्टिक बैग्स का उपयोग नहीं करें। साथ ही पानी, बिजली और अन्न बचाएं। *(दै.न., 05.06.18)*

मनरेगा के अधूरे कार्य जल्द पूरे हों

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मनरेगा में अधूरे पड़े 4 लाख 22 हजार कार्यों को जून 2018 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की धीमी रफ्तार पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जरूरत हो तो काम पूरे करने के लिए अभियान भी चलाया जाए।

राठौड़ ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के साथ स्थाई निर्माण के कार्य हो सकें। उन्होंने मनरेगा में प्रदेश के तीन हजार से अधिक स्मार्ट विलेजों में 17 तरह के किए जाने वाले कार्यों की तत्काल स्वीकृतियां जारी करने के भी निर्देश दिए। *(दै.न., 20.04.18)*

मुफ्त इलाज पर छह गुना ज्यादा खर्च

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दावा किया है कि निःशुल्क इलाज के मामले में हमारी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के मुकाबले छह गुना ज्यादा खर्च किया है।

पिछली सरकार ने मुफ्त दवा योजना पर केवल 300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमारी सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट तो दिया ही, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक 1300 करोड़ रुपए से आमजन को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई। इस तरह लोगों के निःशुल्क इलाज पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। *(दै.न., 05.06.18)*

हर प्रत्याशी की संपत्ति की होगी जांच

आगामी आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में सभी प्रत्याशियों पर अब आयकर विभाग नजर रखेगा। ऐसा पहली बार होगा, जब आयकर विभाग प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय हलफनामे में घोषित उनकी आय और संपत्तियों के ब्योरे की जांच करेगा।

यह पहल उस योजना का हिस्सा होगी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तैयार किया है। अगर प्रत्याशियों द्वारा दिया गया ब्योरा सही नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। *(रा.प., 29.06.18)*

किसानों के फायदे की कई योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों को कम लागत में अच्छी कमाई हो सके, इसके लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए ज्यादा लाभप्रद बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को फसल उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बेहतर करने और किसानों के उत्पादों की खरीद व्यवस्था को लाभदायक बनाने की दिशा में भी ठोस पहल की गई है। किसानों की आय बढ़ सके इसके लिए सरकार पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। *(न.नु., 27.04.18)*

आमजन को मिला बेहतर इलाज

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी वजह से आज समाज के हर तबके को अच्छे से अच्छा इलाज मिलना संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने के बाद प्रदेशभर में अच्छी चिकित्सा तक आमजन की पहुंच संभव हो सकी है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 20 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है। *(दै.न., 19.04.18, 03.05.18)*

मुद्रा योजना से 12 करोड़ लोगों को फायदा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश के 12 करोड़ नागरिकों को छह लाख करोड़ रुपए की ऋण राशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन वर्ष की अवधि में वितरित की गई है। इसमें 74 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है, जिन्होंने स्वरोजगार के लिए यह ऋण लिया है।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से देश में स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक के पास जाकर स्वरोजगार के लिए दस लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है। इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2015 को की गई थी। *(न.नु., 04.06.18)*

भारत बना तीसरा बड़ा सोलर मार्केट

भारत सोलर ऊर्जा के मामले में 2017 में तीसरा सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है और इस मामले में चीन तथा अमेरिका से पीछे है। मरकॉम कम्युनिकेशंस इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह कहा है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत तीसरा सबसे बड़े सोलर बाजार के रूप में उभरा है। भारत ने 2017 में रिकॉर्ड 9600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं लगाईं। यह 2016 में 4300 मेगावाट के मुकाबले दोगुना से भी अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत वृद्धि से देश की सोलर ऊर्जा की स्थापित क्षमता दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार 19600 मेगावाट हो गई।

वर्ष 2017 में बड़ी कंपनियों ने एकीकरण शुरू किया क्योंकि भारत आपूर्तिकर्ताओं और वेंडरों के लिए दुनिया में एक तहत्वपूर्ण सोलर बाजारों के रूप में उभरा है। *(न.नु., 16.05.18)*

देश का हर गांव हुआ रोशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अप्रैल 2018 को देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए दावा किया है कि मणिपुर के लेइसांग गांव सहित देश के ऐसे तमाम गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, जो अभी तक रोशनी से अछूते थे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सभी 597464 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। मोदी सरकार के सत्ता संभालने के वक्त 18452 गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। हालांकि, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) के अनुसार अभी देश के सात करोड़ पांच लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। लोगों से घरों में बिजली कनेक्शन लगवाने को कहा गया है। *(दै.भा. एवं रा.प., 30.04.18)*

बिजली के तार होंगे भूमिगत

स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर शहर की चारदीवारी में झूलते और गुच्छेनुमा बिजली के तारों को भूमिगत करने का काम शुरु कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत दो चरणों में काम होगा जिस पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

इस परियोजना में तमाम बड़ी-छोटी गलियों में तारों को भूमिगत किया जाएगा। डक्टिंगनुमा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें इन केबलों को बिछाया जाएगा। अभी कई जगह पहले से ही यह काम किया जा चुका है। इससे दुर्घटनाओं व आगजनी के समय होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकेगी साथ ही तारों के भूमिगत होने से शहर की सौन्दर्यता में भी निखार आएगा। *(दै.न., 06.05.18)*

बिजली चोरी रोकी, छीजत हुई कम

प्रदेश में बिजली कंपनियों ने बिजली की बर्बादी और चोरी पर नियंत्रण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिन फीडरों पर बिजली चोरी का रिकॉर्ड नहीं सुधर रहा था वहां कटौति लागू कर दी गई। 24 घंटे की जगह वहां 8 घंटे सप्लाई दी गई। इससे बिजली खपत रुकी। दूरस्थ इलाकों में अवैध रूप से लगे ट्रांसफार्मरों को हटाया गया। बिजली चोरी करने वालों की वीसीआर भरी गई और गिरफ्तारियां हुई और कोर्ट में चालान हुए। इससे बिजली चोरी रुकी साथ ही बिजली की बर्बादी भी कम हुई और रेवन्यू बढ़ा। बिजली कंपनियों की यह उपलब्धि उपभोक्ताओं के लिए सुकून भी लेकर आई है। घोषणा की गई है कि प्रदेश के 125 लाख बिजली कनेक्शनों पर अगले एक साल तक बिजली महंगी नहीं होगी। *(दै.भा., 04.06.18)*

विद्युतीकरण क्षेत्र में भारत ने किया अच्छा काम: विश्व बैंक

घर-घर बिजली पहुंचाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए कामों की विश्व बैंक ने सराहना की है। विश्व बैंक की हाल ही जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 85 प्रतिशत आबादी तक बिजली पहुंच गई है। वर्ष 2010 से 2016 के मध्य भारत ने प्रति वर्ष तीन करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराई है।

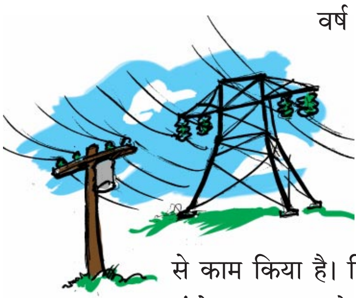

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शेष 15 फीसदी आबादी तक बिजली की सुविधा मुहैया कराना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि, अब जहां तक बिजली पहुंचानी बाकी है वह देश के दूर-दराज वाले इलाके हैं। बीते कुछ सालों में सरकार ने इस दिशा में काफी तेजी से काम किया है। विश्व बैंक ने इस दिशा में सरकार के प्रयासों को काफी संतोषजनक माना है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद दर्शाई गई है कि वर्ष 2020 तक सरकार देश के हर घर में बिजली की सुविधा मुहैया करा देगी। *(न.नु. एवं दै.न., 05.05.18)*

वायु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित

देश की वायु ऊर्जा क्षमता वर्ष 2022 तक बढ़कर 60 गीगावाट हो जाने की संभावना है। यह जानकारी इंडियन विंड टर्बाइन मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ने देते हुए कहा है कि सरकार ने 2022 तक वायु ऊर्जा का 60 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारत का वायु ऊर्जा बाजार लगातार प्रगति पर है और प्रतिस्पर्धी बोली के बाजार में देश में क्लीन ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है। यह ऊर्जा आज अधिक विश्वसनीय और एफोर्डेबल हो गई है। आईडब्लूटीएमए के अध्यक्ष तुलसी तांती ने एक व्यक्तव्य में कहा है कि वर्ष 2017-18 के दौरान वायु ऊर्जा उद्योग में नया बदलाव आया है जो अब प्रतिस्पर्धी बोली के युग में प्रवेश कर गया है। उद्योग तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है और उसके पास अच्छी मात्रा में आदेश उपलब्ध है। *(न.नु., 13.04.18)*

बिजली गुल मामलों पर सख्ती

राजधानी में तकनीकी कारणों के अलावा अधिकारियों की लापरवाही से अब बिजली गुल हुई तो उन्हें 'करंट' लगेगा। यानी निलम्बन व दूसरी कार्रवाई के अलावा उन्हें शहर बदर भी किया जा सकता है।

पिछले कुछ माह से राजधानी में बार-बार हो रही बिजली गुल और उपभोक्ताओं को उचित जवाब नहीं मिलने की खबरों के बाद जयपुर डिस्कॉम प्रबन्धन ने यह कदम उठाया है। शहर के बिजली बेड़े पर नजर रखने के लिए तकनीकी निदेशक नवीन अरोड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। *(रा.प., 26.06.18)*

पानी का गंभीर संकट–नीति आयोग

देश में 60 करोड़ लोगों को पानी की गंभीर किल्लत झेलनी पड़ रही है। देश की 75 फीसदी आबादी को पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। इसके बावजूद जल प्रबंधन को लेकर कई राज्य गंभीर नहीं है। ये बात नीति आयोग द्वारा हाल ही जारी 'समेकित जल प्रबंधन सूचकांक' रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि गांवों में 84 फीसदी आबादी जलापूर्ति से वंचित है। जिन्हें पानी मिल रहा है उसमें 70 प्रतिशत प्रदूषित पानी है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है। रिपोर्ट में जल प्रबंधन को लेकर राज्यों की रैंकिंग बताई गई है। जल प्रबंधन में टॉप 10 राज्यों में गुजरात टॉप पर है, जबकि राजस्थान 10वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार का जल प्रबंधन में प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। *(दै.भा., 15.06.18)*

नीति आयोग चिंतित मगर ...

नीति आयोग ने पानी के मामले में राजस्थान को रेड जोन में रखा है। इसमें भी जयपुर की स्थिति तो ज्यादा ही खराब बताई गई है। राजधानी में रोजाना लाखों लोग पानी के लिए परेशान होते हैं, लेकिन जिम्मेदार बेफिक्र हैं। उन्हें न अंधाधुंध दोहन की चिंता है और न बेखौफ होते पानी माफिया पर लगाम कसने की परवाह।

आमजन तो दूर वीआईपी इलाकों में भी आसानी से पानी उपलब्ध नहीं होता। हालत बिगड़ने के बावजूद जलदाय विभाग के पास न इच्छाशक्ति है और न ही कोई ठोस योजना। नीति आयोग के चार दिन के अध्ययन के बाद नतीजा यह सामने आया। *(रा.प., 17.05.18)*

हर साल एक मीटर डूब रहा है पानी

प्रदेश में अति दोहन से पानी 'पाताल' में पहुंच गया है। हर साल प्रदेश में 900 सरकारी और 4500 से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल खोदते समय ही दम तोड़ देते हैं। जोधपुर और बीकानेर में तो कई जगह 1500 फीट गहराई तक खोदने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है।

भूजल विभाग व जलदाय विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जमीन में पानी का स्तर 167 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है। प्रदेश के 295 वाटर ब्लॉक में से करीब 200 डार्क जोन में जा चुके हैं।

ट्यूबवेल खोदने पर पाबंदी व रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी खास फर्क नहीं पड़ा है। प्रदेश के बांदीकुई और राजगढ़ सहित अन्य कई कस्बों में धरती का पानी रीत गया है। बांदीकुई में रोज 10 किमी दूर से पानी टैंकरों से लाकर सार्वजनिक वितरण की टंकियों में डाला जाता है। जयपुर में 1000 फीट तक की गहराई में भी पानी नहीं मिला है। *(दै.भा., 01.06.18)*

पानी की दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी

प्रदेश में एक साल तक पानी की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक अप्रेल से पानी की दरों में की गई 10 फीसदी बढ़ोतरी के आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बढ़ी दरें वापस लेने के फैसले का प्रदेशभर के करीब 65 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव रजत कुमार मिश्र ने बताया कि इसके लिए जलदाय विभाग ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब एक अप्रेल, 2018 से बढ़ी दरें किसी भी तरह के पेयजल शुल्क पर लागू नहीं होगी। *(दै.न., 12.04.18)*

नजीर बना जल स्वावलंबन अभियान

राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में बेमिसाल काम हुआ है। जिस प्रदेश को लोग सूखे और अकाल के कारण जानते थे आज वही प्रदेश इस अभियान में हुए सफल जल संरक्षण कार्यों के लिए देश और दुनिया में एक नजीर बन चुका है। प्रदेश में इस अभियान के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। जिसमें अब तक 2 लाख 61 हजार जल संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है और 88 लाख पौधे लगाए गए हैं।

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया है कि प्रदेश को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह अभियान काफी सफल रहा है। ब्रिक्स देश व आस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग रिवर बेसिन में भी पानी बचाने के लिए इस अभियान को अपनाया गया है। इसी साल सितंबर में शुरू होने वाले चौथे चरण में 4000 गांवों में एक लाख 25 हजार से ज्यादा जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे। *(दै.भा. एवं दै.न., 19.05.18)*

धड़ल्ले से बिक रहा जनता का पानी

जलदाय विभाग ने राजधानी में जिन टैंकरों को जरूरतमंदों के लिए पानी की व्यवस्था बनाने के लिए लगा रखा है वे जनता के पानी से पैसे बना रहे हैं। ये टैंकर पंप हाउसों से जनता के नाम पर्ची कटाकर पानी तो भर रहे हैं, लेकिन इसे बाजार में बेच रहे हैं। पर्ची कटने के बाद कुछ समय तक तो व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन बाद में यह पानी बिकने लग जाता है। टैंकर चालक बीसलपुर के पानी को 300 रुपए व सादे पानी को 250 रुपए तक में बेच रहे हैं।

सरकारी विभाग एक टैंकर के बदले ठेकेदार को 132 रुपए का भुगतान करता है। लेकिन ठेकेदार इसे बाजार या निर्माणाधीन मकानों में 300 रुपए तक में बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। *(रा.प., 01.05.18, 10.05.18)*

राजस्थान के पानी में यूरेनियम

राजस्थान में भूजल के बढ़ते दोहन से पानी की समस्या तो पहले से ही विकराल बनी हुई है, अब अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट में हुए खुलासे से यह चिंता का कारण बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों के भूजल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से ज्यादा यूरेनियम पाया गया है।

यह पानी कई बीमारियों को जन्म देता है। चिकित्सकों के अनुसार ऐसा पानी किडनी व लीवर की बीमारियों के अलावा कैंसर भी पैदा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है राजस्थान के 33 जिलों में से 26 जिले डार्क जोन में हैं। प्रदेश में 248 भूजल ब्लॉक में से 164 डार्क जोन में है। अलवर के सभी 14 ब्लॉक डार्क जोन में बताए गए हैं। *(दै.भा., 09.06.18)*

महिलाओं को मिले उनके वाजिब हक: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में कामकाजी महिलाओं का अनुपात बढ़ाने की अपील की है।

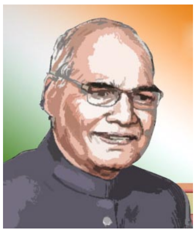

उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र को महिलाओं के अनुकूल और लैंगिक रूप से संवेदनशील आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में महिलाओं को शामिल करने की बजाय उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं कार्यस्थल और घर पर विविध तरीकों से काम करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती हैं। लेकिन जब यह बात व्यवसाय और वाणिज्य पर आती है तो यह खेदजनक है कि महिलाओं को उनका श्रेय नहीं दिया जाता। ऐसी स्थितियां बनाने की जरूरत है जहां अधिक से अधिक बेटियों और बहनों की गिनती श्रम बल में हो सके। *(दै.न., 06.04.18)*

महिला सुरक्षा मिशन लाएगी सरकार

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में व्याप्त चिंताओं का एक साथ समाधान करने के मकसद से सरकार राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन शुरू करने की योजना बना रही है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस मिशन में संबंधित विभागों को भी जोड़ा जाएगा तथा वे कुछ विशेष कार्य हाथ में लेकर उनका समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करेंगे। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के माध्यम से महिलाओं को खासकर नाबालिक बच्चियों के साथ होने वाले अपराध के खिलाफ प्रभावी एवं विश्वसनीय जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए समयबद्ध ढंग से कदम उठाए जाएंगे। बलात्कार और महिला सुरक्षा के अन्य मामलों में समयबद्ध ढंग से विवेचना एवं अभियोजन चले इसकी निगरानी की जाएगी तथा जागरूकता के लिए मीडिया अभियान चलाया जाएगा। *(दै.न., 11.06.18)*

उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ाया

केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़ा दिया है। योजना के तहत पहले 5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने थे, जिसे बढ़ाकर अब 8 करोड़ कर दिया गया है।

राजस्थान में पहले 19.17 लाख परिवारों को यह कनेक्शन दिया जाना था। अब योजना का दायरा बढ़ने से करीब 26.93 लाख परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। योजना में अब प्रधानमंत्री आवास योजना व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों सहित वनवासी, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को भी शामिल किया गया है। *(रा.प., 06.05.18)*

मातृ मृत्युदर में आया सुधार

मातृ मृत्युदर के लिहाज से देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में शामिल राजस्थान हालिया रिपोर्ट में 45 अंकों का सुधार कर पाया है। प्रदेश की मातृ मृत्युदर अब 244 से घटकर 199 पर आ गई है। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड सुधार में 84 अंकों की छलांग के साथ 285 से 201 अंक पर पहुंच गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश पहले से शिशु-मातृ मृत्युदर के लिहाज से देश के फिसड्डी राज्यों में है। केंद्र की ओर से किए जाने वाले सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ओर से भारत में 2014-16 के बीच मातृ मृत्युदर की स्थिति पर जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार राज्य में प्रति एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की 199 मृत्युदर है। सुधार की दृष्टि से राजस्थान को भारी सुधार वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। *(रा.प., 09.06.18)*

वृद्धजन कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से की गई बजट घोषणा की पालना में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में 80 साल से अधिक आयु के वृद्धजन (महिला व पुरुष) अब निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही उनके एक सहयोगी को भी किराए में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

निगम की बसों में यात्रा के लिए रियायत व छूट प्राप्त करने वाले 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज प्रशासन द्वारा स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। *(रा.प. एवं दै.न., 24.04.18)*

स्कूलों में बच्चों को मिलेगा दूध

अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को 2 जुलाई 2018 से पोषाहार के साथ सप्ताह में तीन बार उच्च गुणवत्तायुक्त ताजा दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को 150 एम.एल. एवं कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों को 200 एम.एल. दूध दिया जाएगा। यह योजना छात्र-छात्राओं के पोषण और उनके उचित विकास से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे राज्य के पशुपालक और दुग्ध उत्पादक ग्रामवासी भी लाभान्वित होंगे। योजना का राज्य स्तर पर शुभारंभ मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे करेंगी। *(रा.प., 17.05.18)*

हर जिले में खुलेंगे पॉक्सो कोर्ट

अगले छह महीनों में राज्य के हर जिले में पॉक्सो कोर्ट खुल जाएंगे। सरकार ने यह फैसला दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से लिया है। जिन 11 जिलों में पॉक्सो मामलों की सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, वहां छह महीनों के अंदर-अंदर पॉक्सो कोर्ट खुल जाएंगे।

बाकी बचे 21 जिलों में चरणबद्ध तरीके से तीन साल के भीतर कोर्ट खोले जाएंगे। यह दुष्कर्म पीडिताओं को धीमे न्याय के खिलाफ दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जीत है। मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता के स्तर पर हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। *(दै.भा., 15.06.18)*

सड़क सुरक्षा

शराब पीकर वाहन चलाने पर जेल

सावधान! अगर आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो अब ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की कार्रवाई करने के साथ कोर्ट में पेशी करके आपको जेल भी भेज सकती है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्ती करने के कारण जयपुर शहर में 22 फीसदी सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा है। खास बात यह है कि इस साल शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए 59 लोगों को जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी है। पिछले छह माह में ट्रैफिक पुलिस ने 10 हजार से ज्यादा वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने पर पकड़ा है। *(दै.भा., 27.06.18)*

जान की दुश्मन है तेज रफ्तार

प्रदेश में 80 फीसदी सड़क हादसों में वाहन की तेज रफ्तार जान की दुश्मन बन रही है। सड़क पर गड्ढ़े और खराब इंजीनियरिंग से भी लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से वर्ष 2017 में हुए सड़क हादसों के कारणों के कराए गए विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है। इसके अनुसार 2017 में 10 हजार 444 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, जिसमें 8440 का कारण वाहन की बेकाबू रफ्तार है। जान गंवाने वालों में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और वे मौत के शिकार हो गए। रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस, पीडब्लूडी, जेडीए और नगर निगम की मदद से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की यातायात शाखा ने काम शुरू कर दिया है। *(रा.प., 15.05.18)*

जन स्वास्थ्य

प्रदेश में तैयार हों नए डॉक्टर

प्रदेश में कम से कम 77 हजार 122 डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को मिलाकर 38 हजार 142 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान में जिस संख्या में डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, उस मौजूदा रफ्तार को कम से कम चार गुणा करने की जरूरत है। तभी हम 2035 तक वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्लूएचओ) के मानकों पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि कि डब्लूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों तक पहुंचना असंभव सा है, लेकिन सरकार द्वारा कुछ बड़े निर्णय करके प्रदेश सहित देशभर में हालात सुधारे जा सकते हैं।

राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट में विशिष्ठ सचिव रह चुके आईएएस डॉ. पृथ्वीराज ने अपनी रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। उनका रिसर्च पेपर आने वाले दिनों में यूएसए की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस में पेश होगा। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि अभी प्रदेश में एक हजार की जगह 10 हजार की आबादी पर एक सरकारी डॉक्टर उपलब्ध है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक हजार की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। इसमें सरकारी और प्राईवेट दोनों शामिल है। लगभग ये ही हालात देशभर में हैं। *(दै.भा., 22.06.18)*

पर्यावरण

इस साल लगाएं रिकॉर्ड पेड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करते हुए कहा है कि इस वर्ष बरसात के मौसम में रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में विश्व में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रतीक है।

मोदी ने कहा कि कम गुणवत्ता वाली प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से प्रकृति, जनस्वास्थ्य, वन्य प्राणियों व पशु-पक्षियों पर बुरा असर पड़ रहा है। हमें प्रकृति की रक्षा के प्रति संवेदनशील और सहज स्वभाव से संस्कारित होना चाहिए। *(दै.न., 28.05.18)*

भारत ने वैश्विक नेतृत्व दिखाया

विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत में हुए कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बताते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने इसके लिए भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने 'एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक' को 2022 तक समाप्त करने की घोषणा कर अपने 'वैश्विक नेतृत्व' को दिखाया है।

उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने इस तरह के प्लास्टिक को 2022 तक भारत में समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। *(न.जु., 10.06.18)*

वित्तीय सेवाएं

बढ़ता जा रहा है बैंकों का 'बट्टा खाता'

देश में बैंकों के कर्ज डूबने और फंसने की समस्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ों पर गौर करें, तो बीते चार वर्षों में इसमें और भी ज्यादा तेजी आई है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के आंकड़ों के मुताबिक बीते दस वर्षों में देश के बैंकों ने करीब 4.80 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में जा चुके हैं। फंसे हुए इस कर्ज (बैड लोन) में ज्यादातर हिस्सा सरकारी बैंकों का है, जो तकरीबन चार लाख करोड़ रुपए का है। वहीं, निजी बैंकों का करीब 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज इस श्रेणी में आया है। मई 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद कर्ज को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत और तेज हुई है।

बीते चार साल में करीब 3.57 लाख करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला जा चुका है। इसमें भी सरकारी बैंकों का ही कर्ज ज्यादा डूबा है, जो तीन लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि बैंक समय समय पर अपने ऐसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हैं, जिसकी वसूली संदिग्ध नजर आती है। हालांकि इस खाते में डालने के बावजूद बैंक इस कर्ज की वसूली के प्रयास जारी रखता है। *(रा.प., 16.06.18)*

उपभोक्ता फैसले

न्यूनतम बैलेंस होने के बावजूद बैंक ने खाते से काटी राशि

जोधपुर निवासी शोभा व्यास ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, जोधपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उनका एक खाता एसबीआई (तब एसबीबीजे) में खुला हुआ है। तब बैंक के नियमानुसार खाते में न्यूनतम बैलेंस 1000 रुपए रखना जरूरी था। काफी समय बाद जब उन्होंने अपनी पासबुक अपडेट कराई तो मालूम हुआ कि बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस होने के बावजूद उनके खाते से 2083.69 रुपए की कटौती कर दी गई है। उन्होंने बैंक प्रबंधक से इसकी जानकारी चाही तो कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही समाधान किया गया। थक-हारकर उन्होंने बैंक को विधिक नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलते ही बैंक अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध काटी गई राशि 2083.69 रुपए उनके खाते में जमा कर दी। बैंक द्वारा काटी गई इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं दिया गया। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है।

मामले कि सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने बैंक द्वारा गुपचुप रूप से विधि विरुद्ध की गई कटौती को गैरवाजिब मानते हुए बैंक को सेवा का दोषी ठहराया। मंच ने एसबीआई को राशि कटौती करने की तारीख से खाते में राशि वापस जमा करने की तारीख तक का ब्याज अदा करने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति पेटे 3000 रुपए शोभा व्यास को चुकाने के आदेश दिए है। *(दै.भा., 06.05.18)*

अमेजोन सेलर सर्विस को भारी पड़ा आर्डर कैंसिल करना

जयपुर स्थित मुरलीपुरा निवासी सुनील कुमार शर्मा ने अमेजोन सेलर सर्विस के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच जयपुर-द्वितीय में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने 21 जून 2016 को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए अमेजोन सेलर सर्विस से चार मोबाइल मंगाने के लिए आर्डर दिया था। उन्होंने इन मोबाइलों की पूरी राशि का भुगतान भी ऑनलाइन कर दिया था। लेकिन आर्डर के 12 घंटे बाद ही अमेजोन सेलर सर्विस ने उनके आर्डर को बिना बताए ही कैंसिल कर दिया। उसने आर्डर को क्यों और किन कारणों से कैंसिल किया इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं दी। उन्होंने मंच से निवेदन किया कि इससे उनको मानसिक रूप से क्षति पहुंची है, जिसके लिए उन्हें हर्जाना दिलाया जाए।

मामले की सुनवाई पर जिला उपभोक्ता मंच ने अमेजोन सेलर सर्विस को मोबाइल नहीं भेजने और बिना कोई कारण बताए उनके आर्डर को कैंसिल करने को सेवा दोष माना। मंच ने अमेजोन सेलर सर्विस को आदेश दिया कि वह सुनील कुमार शर्मा को 5000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। मंच ने अपने आदेश में यह हर्जाना राशि दो महीने की अवधि के भीतर अदा करने के लिए कहा है। *(दै.भा., 17.06.18)*

खास समाचार

मिलावट पर उम्रकैद और लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना

खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स एक्ट में संशोधन के प्रस्तावों में यह सिफारिश की है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्स एक्ट में कुल 100 संशोधनों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। खाने में मिलावट पर सख्ती के लिए तो एक नया सेक्शन ही जोड़ने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोई भी शख्स खाने-पीने की चीजों में ऐसा कुछ मिलाता है, जिससे खाने वाले को कोई नुकसान, मृत्यु, घायल अथवा बीमार होने की आशंका हो तो मिलावटखोर को कम से कम सात साल की सजा देनी चाहिए। इसे बढ़ाकर उम्रकैद भी किया जा सकता है। जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़ी सजा का यह प्रावधान किया है। *(दै.भा., 27.06.18)*

खाद्य पदार्थों में बढ़ी मिलावट

प्रदेश में मिलावटखोर बेखौफ होते जा रहे हैं। पिछले सात सालों में खाद्य पदार्थों में मिलावट 10 गुना ज्यादा हो गई। वर्ष 2011 में जहां खाद्य पदार्थों के 267 नमूनों में मिलावट मिली थी वहीं 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 2080 तक पहुंच गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इन मिलावटी नमूनों में 1709 अनसेफ पाए गए, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक की श्रेणी में आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एक भी मिलावटखोर को सजा नहीं दिलवा पाया। इससे मिलावटखोर बेखौफ होकर आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। *(दै.भा., 08.04.18)*

'उदन्त मार्तण्ड' हिन्दी का पहला अखबार

हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' था। कलकत्ता से 30 मई 1826 को एक साप्ताहिक पत्र के रूप में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक व संपादक पंडित जुगल किशोर सुकुल थे। तब अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो समाचार पत्र खूब निकलते थे, किन्तु हिन्दी में एक भी नहीं। भारत में यह दिन हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं।

उदन्तमार्तण्ड

स्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।